

DATE: 10/09/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: IIIrd (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 08 (PARLIAMENT: LOKSABHA & RAJYASABHA)

LECTURE NO. - 08 (EIGHT)

By

OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR

DEPTT. OF POL. SC.

D.B. COLLEGE, JAYNAGAR

LNMU, DARBHANGA

लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य

लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है -

(1) विधायी शक्ति -

सभी तरह के विधेयकों के मामलों में लोकसभा की शक्ति सभा के समान या उससे ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन विधेयक जिसके सम्बंध में अनुच्छेद 110 में उल्लेख है तथा वित्त विधेयक प्रकार - 1 जिसके सम्बंध में अनुच्छेद - 117(1) में उल्लेख है, सिर्फ लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन एवं धन विधेयक के छोड़कर शेष विधेयक के संदर्भ में दोनों सभों में बतौर शक्ति होने की स्थिति में संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अनुसार बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा की मजबूत स्थिति का परिचायक है।

(2) वित्तीय शक्ति -

वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं।

(3) कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति -

कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए सरकार अर्थात् कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है।

कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अन्तर्गत ही लोकसभा संबन्धी लोकसभा सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, आदि की रिपोर्ट पर विचार करती है।

(4) संविधान संशोधन सम्बंधी शक्ति -

संविधान संशोधन के सम्बंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और उसे तभी पारित माना जाता है जब दोनों सदन आपस-आपस अपने-अपने कुल बहुमत तथा उपाध्यत एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के हों- तिहाई बहुमत से पारित कर रहे हैं।

(5) विविध कार्य और शक्ति -

(i) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं।

(ii) लोकसभा और राज्यसभा

मिफकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है।

(iii) राज्यका द्वारा उपराष्ट्रपति को इटाने के लिए पारित प्रस्ताव का अनुमोदन यदि लोकसभा न करे तो उसे इटाने जाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है।

(iv) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पह से इटाने के लिए भी लोकसभा की सहमति आवश्यक है।

इस प्रकार हम लोकसभा के शक्तियों एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यह संसद का प्रभावशाली, शक्ति-शाली एवं अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है।

सम्भावित प्रश्न:

लोकसभा की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए।